भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2288
16 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

तंजावुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी

2288 श्री एस. कल्याणसुन्दरमः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2019 से तंजावुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों की संख्या कितनी है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2019 से तंजावुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अब तक कितनी धनराशि संस्वीकृत और संवितरित की गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राजसहायता की राशि बढ़ाने संबंधी कोई विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, "सभी के लिए आवास" के दृष्टकोण के तहत, देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के आवास प्रदान करने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रयासों में सहायता करता है। भारत सरकार पीएमएवाई-यू के "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) के तहत 1.0 लाख रुपए, साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) और लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के लिए 1.5 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता के रूप में अपना निश्चित हिस्सा प्रदान करती है। डीपीआर के अनुसार आवास की शेष लागत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों

(यूएलबी)/लाभार्थियों द्वारा साझा की जाती है। पीएमएवाई-यू के सीएलएसएस घटक के तहत, ब्याज सब्सिडी के रूप में प्रति आवास 2.67 लाख रुपये तक की अग्रिम सब्सिडी प्रदान की गई थी।

योजना के सीएलएसएस घटक को छोड़कर, इस योजना को 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि वित्तपोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना स्वीकृत सभी आवासों को पूरा किया जा सके।

तंजावुर जिले में, 2015 से कुल 12,942 आवासों को स्वीकृति दे दी गई है, जिनमें से 2019-20 से 4,707 आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है। तंजावुर जिले के लिए शुरुआत से और वित्त वर्ष 2019-20 के बाद से स्वीकृत एवं जारी केंद्रीय सहायता द्वारा स्वीकृत, निर्माणाधीन; पूरे किए गए आवासों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से देश भर के शहरी क्षेत्रों में किफायती लागत पर घर बनाने, खरीदने और किराये पर लेने के लिए एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जा सके। अब तक, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। योजना के दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/operational-guidelines-of-pmay-u-2.pdf पर उपलब्ध हैं। तमिलनाडु राज्य ने अभी तक पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 16-12-2024 **को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या** 2288 **के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

पीएमएवाई-यू के तहत शुरुआत से और वित्त वर्ष 2019-20 से अब तक तमिलनाडु के तंजावुर जिले में वास्तविक और वित्तीय प्रगति का विवरण

क्र. संख्या	विवरण	तंजावुर जिले का विवरण	
		योजना की शुरूआत से	(वित्तीय वर्ष 2019-20 से आज तक) के दौरान
1.	स्वीकृत आवास (सं०)	12,942	4,707
2	निर्माणाधीन आवास (सं०)	12,666	5,443 **
3.	पूर्ण आवास (संख्या)	11,463	7,534 **
4	स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	200.82	77.16
5	जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	203.31*	114.95 **

* इसमें उन आवासों/परियोजनाओं में जारी की गई निधियां शामिल है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है और अन्य चल रही परियोजनाओं में समायोजित निधियों के अधीन है।

** इसमें पूर्ववर्ती वर्षों के निर्माणाधीन, पूर्ण और इन वर्षों में ऐसे आवासों के लिए जारी केंद्रीय सहायता शामिल है।